

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारी बाल विकास पथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अ धकारी बाल विकास पथौरागढ़ के माह 05/2016 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस. राणा AAO श्री र व शंकर AAO एवम श्री वजय कुमार वरि०ले०प० द्वारा दिनांक 06/11/2017 से 17/11/2017 तक श्री एस०के० जौहरी लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

#### भाग-1

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री संदीप कुमार गर्ग AAO तथा श्री अश्विनी कुमार पांडेय AAO, श्री दिनेश कुमार नरवरिया, ऑ डटर द्वारा दिनांक 30/05/2016 से 09/06/2016 तक श्री प्रेमचन्द्र लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2014 से 04/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2016 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
  - (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्र: आगंबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से लाभार्थियों को 1-अनुपूरक पोषाहार 2-स्वास्थ्य परीक्षण 3-संदर्भ सेवाए 4-प्रतिरक्षण टीकाकरण 5-पोषण एवम स्वास्थ्य शिक्षा 6-स्कूल पूर्व शिक्षा (प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवम शिक्षा)। समस्त पथौरागढ़ जनपद।
  - (ii) (इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाय)
- (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(रू. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	00	00	145.95	79.25	2266.32	2163.67	00	169.35
2015-16	00	00	42.26	41.72	245.16	212.54	00	33.16
2016-17	00	00	30.51	24.92	202.97	169.92	00	38.64
2017-18 10/2017 तक	00	00	20.57	17.66	4.44	2.40	00	4.95

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम।	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अ धक्य (+)	बचत(-)
2014-15	आई.सी.डी.एस. का संचालन/ क्रयान्वयन	00	217.00	203.40	00	13.6
	आगनवाडी केंद्र की अवसंरचना सु वधा	00	32.14	20.13	00	12.01
	राज्य/जिला' परियोजना स्तर मशन ई0सी0सी0ई0	00	11.61	11.57	00	0.04
	आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत एससी बाहुल्य ग्रामो मे आगनवाडी केन्द्रो का संचालन	00	52.00	44.47	00	7.53
	आगनवाडी केंद्र भवनो का धनआवंटन(GEN)	00	157.50	00	00	157.50(PLA)
	आगनवाडी केंद्र भवनो का धनआवंटन(एससी)	00	45.00	00	00	45.00(PLA)
	आगनवाडी केंद्र भवनो का धनआवंटन(एसटी)	00	705.50	00	00	705.50(PLA)
	आगनवाडी कार्यकत्रि/सहायिका/ मनी कार्यकत्रि प्र शक्षण	00	44.5	39.84	00	4.66
2015-16	आगनवाडी कार्यकत्रि/सहायिका/ मनी कार्यकत्रि प्र शक्षण		37.25	34.19		3.06
	आगनवाडी केंद्र भवनो का धनआवंटन(एसटी)		1.84	0.24		1.6
	आगनवाडी केंद्र भवनो का धनआवंटन(GEN)		14.00	11.47		2.53
	आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत एससी बाहुल्य ग्रामो मे आगनवाडी केन्द्रो का संचालन		7.3	1.18		6.12
	सूचना शक्षा प्रचार प्रसार		8.00	2.98		5.02
	राज्य/जिला' परियोजना स्तर मशन ई0सी0सी0ई0		11.65	11.26		0.39
	मे ड सन कटस डुलान		0.5	.49		.01
2016-17	आगनवाडी कार्यकत्रि/सहायिका/ मनी कार्यकत्रि प्र शक्षण		9.58	9.20		0.38
2017-18 (10/2017)	00		00	00		00

(ii) इकाई को बजट आवंटन (राज्य एवं केंद्र) द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई केंद्र से धनराश प्राप्त करता है तथा सी श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्तर्गत इकाई आती है, उसे इंगत कया जाय) की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1- .....सचिव.....2. ....निदेशक.....3- ....डी०पी०ओ..... 4-

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित कया जाय)

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विध: लेखापरीक्षा में जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, पथौरागढ़ (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित कया जाय) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास पथौरागढ़ (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित कया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह-12/2006 एवं को वस्तुतः जांच हेतु चयनित कया गया। नन्दा...देवी योजना, वृद्ध महिला पोषण, टीएचआर, क्लक फूड, RUTF, कशोरी शक्ति योजना

(जिस योजना का चयन कया गया उसका नाम अंकित कया जाय) का वस्तुतः विश्लेषण कया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय राशि तथा कार्य की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन किया गया। (प्रतिचयन विध का नाम अंकित कया जाय) के आधार पर कया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II'अ'

(इस भाग में नियमतता से संबंधित मामले/ व शष्ट वषरों के मामले एवं औचित्य से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित किये जाय)

शून्य

भाग-II'ब'

(इस भाग में नियमतता तथा औचित्य दोनों से संबंधित प्राप्त गक लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित होंगे। यदि सम्भव हो, तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उनके महत्व तथा व शष्टता के आधार पर घटते क्रम में बनाया जाय

- 1- ब्याज प्रप्त की धनराश रू. 36,55,915/- को राजकोष में जमा न करना।
- 2- नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत अनियमत भुगतान के परिणामस्वरूप रू. 4.05 लाख की हानि।
- 3- नवीन आगनवाडी केंद्र भवनो के निर्माण एवं पुराने आगनवाडी केंद्र भवनो के उच्चीकरण के कार्य को अपूर्ण रखते हुये रू. 225.35 लाख धनराश को अवरुद्ध रखा जाना।
- 4-RUTF योजना के निर्देशों के अनुपालन में उदासीनता के चलते योजना के उद्देश्यों का वफल रहना।
  1. स्टैन- रू. 2.20 लाख की धनराश को अवरुद्ध रखते हुये कशोरी शक्ति योजना के लाभ से लाभार्थियों को वंचित रखना।

भाग -दो (ब)

प्रस्तर 1:- ब्याज प्राप्ति ₹ 36,55,915/-की धनराश राजकोष में जमा न कया जाना ।

उत्तराखंड शासन के वक्त वभाग के शासनादेश संख्या: U.O. 18/XXVII(6)-टी. सी. ए. 934-2014, दिनांक 21.04.2017 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग के आदेश संख्या: 610/XVII(4)/2017-2(8)2017, दिनांक 26.04.2017 के अनुसार प्रशासनिक वभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनराश बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित कया जाता है और उक्त ब्याज की धनराश राजकोष में जमा न करते हुए प्रयोग में लया जा रहा है। यह एक घोर वतीय अनियम मतता है तथा निर्देशत कया है की जितने भी बैंक खाते है उनमें अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुए तत्काल उक्त धनराश राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जाय।

इसके अतिरिक्त उत्तराखंड शासन शासनादेश संख्या:99/XXVII(14)/2009 दिनांक 03.09.2009 द्वारा भी निर्देशत कया गया था क यदि कसी व शष्ट कारणों के कारण समे कत नि ध से आहरित धनराश का उपयोग न कया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो तब इस प्रकार अर्जित धनराश राजकोष में लेखाशीर्षक -0049-ब्याज प्राप्तियाँ, 04 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ, 800 अन्य प्राप्तियाँ, 12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा कया जाय।

जिला कार्यक्रम अधकारी, पथौरागढ़ के अधलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क इकाई द्वारा पदनाम बैंक खातों में व भन्न योजनाओं की जमा धनराश्यों पर कुल ` 36,55,915/- (सूची संलग्न) का ब्याज अर्जित कया गया था जो लेखापरीक्षा तिथ (नवम्बर 2017) तक बैंक खाते में ही पडा था । उक्त शासनादेशों के अनुपालन में प्राप्त ब्याज की धनराश राजकोष में जमा कया जाना अपेक्षत था परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथ (नवम्बर 2017) तक उक्त ब्याज की धनराश राजकोष में जमा नहीं की गई थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क नियमों की जानकारी के अभाव में ब्याज की धनराश जमा नहीं की जा सकी जिसे यथा शीघ्र जमा करा दिया जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्त की पुष्टि करता है। अत ` 36,55,915/- की ब्याज की धनराश राजकोष में जमा न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

जिला कार्यक्रम अ धकारी, पथौरागढ।  
बैंक खाता संख्या: 0768104000069605.

ति थ	प्राप्त ब्याज की धनरा श ( ं में)
31.03.2016	348238=00
25.06.2016	815744=00
24.09.2016	568182=00
24.12.2016	504213=00
25.03.2017	448062=00
24.06.2017	371605=00
23.09.2017	305900=00
योग -	<b>3361944=00</b>

बैंक खाता संख्या: 0768104000070294.

ति थ	प्राप्त ब्याज की धनरा श ( ं में)
31.03.2016	52800=00
25.06.2016	144794=00
24.09.2016	1971=00
24.12.2016	1990=00
25.03.2017	6391=00
24.06.2017	2074=00
23.09.2017	2094=00
योग -	<b>212114=00</b>

जिला कार्यक्रम अ धकारी, पथौरागढ।  
बैंक खाता संख्या: 4321153975.

ति थ	प्राप्त ब्याज की धनरा श ( ं में)
30.06.2016	22726=00
30.09.2016	11717=00
31.12.2016	11835=00
31.03.2017	11694=00
30.06.2017	11941=00
30.09.2017	11944=00
योग -	<b>81857=00</b>

### भाग -दो (ब)

प्रस्तर 2:- नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत अनियमत भुगतान के परिणाम स्वरूप रु 4.05 लाख की हानि तथा रु 6.30 लाख का संदिग्ध भुगतान।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवासियों को जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जी वत बालक/बालिकाओं ने जन्म लिया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्तें पूरी करते हो चाहे इसके पूर्व उनकी अन्य जी वत संतानें भी हो को दिया जाना है। उक्त योजना के अंतर्गत रु 15000/- की धनराशि तीन कस्तों में प्रदान की जानी है।

योजना के दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की गहनता पूर्वक जांच की जाए एवं उसके बाद जनपद स्तरीय समिति के सम्मुख स्वीकृति हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाए। स्वीकृत लाभार्थियों की सूची की जांच में पाया गया कि स्वीकृत आवेदन पत्रों की जांच ठीक से नहीं की गयी थी। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु 27 आवेदकों द्वारा प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र उनकी जन्मतिथि से पूर्व जारी किए गए थे जो कि जांच का विषय था एवं इस आधार पर उक्त आवेदक योजना के लाभ हेतु अपात्र थे जबकि इन आवेदकों को पात्र मानकर धनराशि का भुगतान किया गया था इस प्रकार 27 लाभार्थियों को किया गया रु 4.05 लाख (15000/- प्रति) का भुगतान अनियमित था। परिणामस्वरूप वभाग को रु 4.05 लाख की हानि हुई। इसी प्रकार 42 लाभार्थियों के जन्म प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि अंकित नहीं थी परंतु तथ्यों की जांच किए बिना उनको लाभान्वित करते हुए रु 6.30 लाख का संदिग्ध भुगतान किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में आपत्त कए जाने पर वभाग ने अपने उत्तर में बताया कि आवेदन पत्रों की जांच संबंधित बाल विकास परियोजना स्तर पर की जानी थी जिसका संकलन जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय द्वारा किया गया, उक्त प्रकरणों की जांच की जाएगी तथा अनियमितता पायी जाने की स्थिति में संबंधित लाभार्थियों से वसूली की जाएगी। वभाग का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्त की पुष्टि करता है।

अतः रु 4.05 लाख की वभागीय हानि तथा रु 6.30 लाख के संदिग्ध भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

### भाग -दो (ब)

प्रस्तर 3:- नवीन आंगनवाड़ी केंद्र भवनो के निर्माण एवं पुराने आंगनवाड़ी केंद्र भवनो के उच्चीकरण के कार्य को अपूर्ण रखते हुए रु 225.35 लाख की धनराश को अवरुद्ध रखा जाना।

जिला कार्यक्रम अ धकारी, पथौरागढ़ के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया की भारत सरकार द्वारा वतीय वर्ष 2014-15 में जनपद पथौरागढ़ में 200 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं 08 पुराने आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के उच्चीकरण कार्य हेतु रु 908.00 लाख (रु 4.50 लाख प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण हेतु एवं रु 1.00 लाख प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के उच्चीकरण कार्य हेतु) की धनराश अवमुक्त करते हुए व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस संबंध में निदेशालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि निर्माण कार्य वतीय वर्ष 2014-15 में पूर्ण कर लिए जाए। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण गुणवत्ता पूर्ण एवं समय सीमा में ही हो इसके लिए संबन्धित जिला कार्यक्रम अ धकारी, खाल विकास परियोजना अ धकारी उत्तरदाई बनाए गए थे। धनराश फरवरी 2015 में जारी होने के कारण इस धनराश को सी डी ओ, डी एम के पी एल ए खाते में रखा गया तथा इसके बाद जनवरी 2016 में उक्त धनराश को वभागीय खाते में डाला गया। उल्लेखनीय है कि 200 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र भवनो के सापेक्ष 195 केन्द्रो का चयन कर धनराश जारी की गयी जब कि शेष 5 केन्द्रो का चयन धनराश निर्गत होने के ढाई वर्ष (30 माह) की अवधि के बाद अतिथित तक नहीं किया गया था, इसी प्रकार उच्चीकरण हेतु प्रस्तावित 8 केन्द्रो का चयन भी लेखापरीक्षा तिथित तक नहीं किया गया था एवं यह धनराश (30.50 लाख)\* इकाई के खाते में अवरुद्ध रखी गयी थी। अ भलेखो की लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त धनराश में से 50% धनराश (4,38,75,000) माह मई/जून 2016 में ग्रामपंचायत के खाते में डाली गयी इसके अतिरिक्त दूसरी कश्त के रूप में 40% धनराश (रु 2,41,20,000) 134 निर्माण केन्द्रो को जारी की जा चुकी थी। धनराश जारी होने के 15-16 माह की अवधि बीत जाने के बाद भी लेखा परीक्षा तिथित तक मात्र 6 भवनो का ही निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था जब कि अवशेष 189 केन्द्रो का निर्माण कार्य अपूर्ण था। जिस कारण रु 225.35 लाख की धनराश इकाई के खाते में अवरुद्ध थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उक्त धनराश निर्माण कार्य से संबन्धित है जिसे केन्द्रो के पूर्ण होने की सूचना पर कश्तों में जारी किया जाना है। निर्माण कार्यो हेतु मनरेगा से डबटे लंग में हुई देरी से निर्माण कार्यो के पूर्ण होने में बिलंब हो रहा है। कार्यो को शीघ्र पूर्ण किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तकनीकी कारणो के आधार पर 5 केन्द्रो का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है इस संबंध में निदेशालय को अवगत कराया जा रहा है। 08 भवनो के उच्चीकरण का कार्य शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्त की पुष्टि करता है अतः नवीन आंगनवाड़ी केंद्र भवनो के निर्माण एवं पुराने आंगनवाड़ी केंद्र भवनो के उच्चीकरण के कार्य को अपूर्ण रखते हुए रु 225.35 लाख की धनराश को अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।



## भाग -दो (ब)

**प्रस्तर 4:- RUTF योजना के निर्देशों के अनुपालन में उदासीनता के चलते योजना के उद्देश्यों का वफल रहना।**

शासनादेश सं० 81/XVII (4) 2017-एस (126)/2016, दिनांक 12/01/2017 के अंतर्गत राज्य के समस्त कुपोषित बच्चों हेतु RUTF (Ready to use Therapeutic Food) के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया, जिसके अनुसार अतिकुपोषित बच्चों को ऊर्जा नामक खाद्य सामग्री को आगनवाड़ी केन्द्रों पर वितरित किया जाएगा तथा यह पूर्व में आवंटित किए जाए वाले THR से अतिरिक्त होगा। प्रथम चरण में यह अतिकुपोषित बच्चों को खिलायी जायेगी। 06 माह से 01 वर्ष आयु के बच्चों को दिन में 02 बार, 50ग्राम प्रतिदिन खिलायी जायेगी। माह में 25 दिवसों हेतु 01 बच्चे को 1.250 किलोग्राम की आवश्यकता होगी जिस परव्यय रू० 136.25 होगा। इसके अलावा प्लास्टिक के डिब्बे व चम्मच सहित व्यय रू० 251.25 होगा। इसी प्रकार 01 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चों को दिन में दो बार, 100 ग्राम प्रतिदिन खिलायी जायेगी। प्रतिमाह में 25 दिवसों हेतु 01 बच्चे को 2.50 किलोग्राम की आवश्यकता होगी, जिस पर व्यय रू० 272.50 होगा। प्लास्टिक के डिब्बे व चम्मच सहित व्यय रू० 387.50 होगा। अतिकुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में आने के बाद दो माह तक ऊर्जा को खिलाया जाना है। इस प्रकार कुल 3 माह ऊर्जा खाद्यन खिलाया जाना है। जनपद में ऊर्जा तैयार करने हेतु स्वयं सहायता समूह का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। योजना हेतु निदेशालय आईसीडीएस, उत्तराखंड के पत्र सं०2391/बजट-4073/2016-17, दिनांक 17/01/2017 द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, पिथरागढ़ को RUTF योजना के क्रियान्वयन हेतु रू० 16800/- आवंटित किए गये थे।

इकाई के RUTF से संबन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि इकाई द्वारा जनपद में 06 माह से 05 वर्ष तक के 12 अतिकुपोषित बच्चों को चिन्हित किया , जिसमें से एक बच्चा 06 माह से 1 वर्ष की आयु का था , शेष 11 बच्चे 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु के थे। इन बच्चों को मार्च 2017 में कुल रू० 4901.25 की एक बार ऊर्जा खाद्य सामग्री प्रदान की गयी, शेष धनराशि को समर्पित का दिया गया जबकि RUTF के दिशानिर्देशानुसार बच्चों एक बार ऊर्जा खाद्य सामग्री देने के पश्चात अगले दो माह तक भी ऊर्जा खाद्य सामग्री देना था जिससे कि बच्चे अतिकुपोषण से पूरी तरह मुक्त हो सके। अभिलेखों में पाया गया है कि एक माह ऊर्जा खिलाने के पश्चात अतिकुपोषण से मुक्त बच्चों की संख्या शून्य है। इस प्रकार तीन माह तक ऊर्जा खाद्य सामग्री न खिलाया जाना योजना के उद्देश्यों के उद्देश्यों को विफल करता है।

इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि योजना हेतु बजट जनवरी माह के अंत में प्राप्त जारी होने के कारण तथा योजना की कार्यवाही में समय लगने के कारण मार्च माह में प्रथम बार RUTF दिया गया। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि RUTF योजना के निर्देशानुसार अतिकुपोषित बच्चों को एक माह 'ऊर्जा' पोषक तत्व खिलाने के पश्चात, अगले दो माह तक 'ऊर्जा' पोषक तत्व खिलाया जाना था, जिससे अतिकुपोषित बच्चे, अतिकुपोषण से मुक्त हो सके। परन्तु इकाई योजना के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रही, जिससे चयनित 12 अतिकुपोषित बच्चे, अतिकुपोषण से मुक्त नहीं हो सके। इकाई द्वारा तीन बच्चों के अतिकुपोषण से मुक्त होने के सम्बन्ध कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया, साथ ही अगले दो माह हेतु बच्चों को 'ऊर्जा' पोषक तत्व प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं किया गया।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

## STAN

**प्रस्तर 1:- ₹ 2.20 लाख की धनराश को अवरूद्ध रखते हुए कशोरी शक्ति योजना के लाभ से लाभार्थियों को वंचित रखना।**

निदेशालय आई० सी० डी० एस० उत्तराखंड, देहरादून के पत्र सं० सी०-2846/बजेट-4073/2016-17, दिनांक 27.02.2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में कशोरी शक्ति योजना का संचालन हेतु इकाई को ₹ 2,20,000/- आवंटित किये गये जिसमें कार्ययोजना संलग्न कर निर्देश दिये गये थे कि कार्ययोजना के अनुसार अपने जनपद में जिला स्तरीय कमेटी के गठन कि कार्यवाही पूर्ण करते हुए कार्ययोजना के अनुसार गतिविधिया प्रारम्भ करना सुनिश्चित करे एवं प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराये।

कार्ययोजना के अनुसार कशोरियों को व्यवसायिक कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जायेगा इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर सिलाई, कढ़ाई, पोषण से संबन्धित व्यवसायो, इत्यादि कि जानकारी भी दी जायेगी। कशोरियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण, कशोरी दिवस/स्वास्थ्य दिवस के आयोजन में ए०एन०एम० के द्वारा प्रत्येक कशोरी का वजन लेकर एवं हीमोग्लोबिन का परीक्षण किया जाएगा एवं आई०एफ०ए०की 100 टबलेट के साथ अल्बेण्डजल कि एक गोली वितरण/सेवन हर 6 माह में सुनिश्चित किया जाएगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, पिथौरागढ़, के वर्ष 2016-17 के कशोरी शक्ति योजना से संबन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 27 फरवरी, 2017 में आवंटित ₹ 2,20,000/- की धनराशि को मार्च, 2017 में उत्तराखंड शासन की अनुमति से मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ के पी०एल०ए० खाते में रखा गया (29.3.2017) जिसकी अनुमति शासन द्वारा इस शर्त के साथ दी गयी थी कि phased manner में वित्त विभाग कि सहमति से ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। आगे अभिलेखों कि संवीक्षा में पाया गया कि आतिथि तक उक्त धनराशि को पी०एल०ए० खाते से आहरित कर कशोरी शक्ति योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया, जिससे कशोर शक्ति योजना से मिलने वाले व्यवसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण तथा आई०एफ०ए० टैब्लेट से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ से लाभार्थी वंचित है। इस प्रकार विभागीय उदासीनता के चलते आतिथि तक कशोरी शक्ति योजना का क्रियान्वयन न हो सका तथा ₹ 2,20,000/- की धनराशि विभाग के पास अवरूद्ध है।

इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि धनराशि PLA खाते में रक्षित है जिसके आहरण कि स्वीकृति शासन में लंबित है। धनराशि के आहरण उपरान्त जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 8 माह से अधिक कि अवधि बीत जाने के बाद भी धनराशि को phased manner में, विभागीय उदासीन के चलते आहरित नहीं किया गया और न ही जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। धनराशि के आहरण कि स्वीकृति शासन में लंबित रहने के सम्बन्ध में इकाई द्वारा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

**भाग-III**

(इस भाग में वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ'	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या
2016-17/34	शून्य	01,02,03
2014-15/126	शून्य	01,02

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या वचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
वगत लेखा प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा तैयार की जा रही थी, जिसे उच्च अधिकारियों की संस्तुति के पश्चात् लेखा परीक्षा कार्यालय को भेजा जायेगा।				

**भाग-IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाय)

शून्य

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु.....जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास पथौरागढ़..... तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

- (i) शून्य
- (ii) शून्य
- (iii)

2. सतत अनियमितताएं:

- (i) शून्य
- (ii)

3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
----------	-----	-------

(i)	श्रीमति राधिका हयडू	01.05.2016 से 19.12.2016
-----	---------------------	--------------------------

(ii)	श्री मुकुल चौधरी	19.12.2016 से वर्तमान तक
------	------------------	--------------------------

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास पथौरागढ़... को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामाजिक क्षेत्र